पंजीकृत संख्या 72/54-55
www.rssrashtriya.org

।। वन्दे मातरम् ।।

Tel. : 0141-2377799
Fax : 0141-2362212
E-mail : rss.rashtriya@gmail.com

# राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर-302 001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द्र सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, उमराव लाल वर्मा

Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, R.R.K.M. & E.I.,

| प्रहलाद शर्मा<br>अध्यक्ष<br>9414056109 | रामावतार शर्मा<br>सभाध्यक्ष<br>9166616080 | देवलाल गोचर<br>महामंत्री<br>9414403756 |
|---|---|---|

क्रमांकः 874

दिनांकः 31.12.16

आदरणीय प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यगण एवं
जिलाध्यक्ष, जिलामंत्री, महिला मंत्री, संगठन मंत्री महोदय।

सादर वन्दे!

आप सभी को विदित है कि केन्द्र सरकार द्वारा दि. 01.01.2016 से सातवाँ वेतनमान लागू कर दिया गया है। अनेक राज्य सरकारों द्वारा भी सातवें वेतनमान की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है मगर राजस्थान सरकार इस दिशा में अब तक न केवल मौन है अपितु वरिष्ठ अध्यापक पद की स्थिरीकरण की विसंगति सहित छठे वेतनमान में सभी संवर्गों के कार्मिकों का देय वेतनमानों की विसंगतियों पर भी उदासीनता ही दिखा रही है। शिक्षकों को वर्तमान में छठे वेतन आयोग के तहत दिये जा रहे पे-बैण्ड एवं ग्रेड-पे केन्द्रीय वेतनमान के समतुल्य नहीं किये जाने से पूर्व ही सातवें आयोग की सिफारिशें लागू किये जाने से सभी संवर्गों के कार्मिकों को भारी हानि होने की आशंका है। अतः पूर्व में रही विसंगतियों को दूर किया जाना अति आवश्यक है। संगठन के प्रयासों से सन् 2013 में भा.ज.पा. के चुनाव घोषणा-पत्र में भी इन विसंगतियों को दूर किये जाने का उल्लेख किया गया था। इस अवधि में अन्य अनेक संवर्गों की विसंगतियों को दूर किया गया है अथवा दूर किये जाने की प्रकिया चल रही है मगर शिक्षकों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की उदासीनता एवं उपेक्षा खेदजनक है।

संगठन ने इन विसंगतियों को लेकर माननीय शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव एवं वित्त सचिव स्तर तक अनेक बार वार्ताएँ भी की मगर केवल आश्वासन ही प्राप्त हुए। कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। संगठन की स्थाई समिति से विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि 02 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव तथा शिक्षा सचिव से भेंट कर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने तथा लागू करने से पूर्व छठे वेतन आयोग में शिक्षकों के विविध संवर्गों के साथ रही विसंगतियों को अविलम्ब दूर करने की मांग की जाये। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि आगामी 10 जनवरी 2017 को राज्य के समस्त जिलो में जिला कलक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भिजवाया जाकर उनका ध्यान आकृष्ट किया जाये।

ज्ञापन के प्रारूप की प्रति इस पत्र के साथ भिजवा कर आग्रह है कि 10 जनवरी 2017 को आप अपने-अपने जिलों में जिला कलक्टर कार्यालय पर दोपहर बाद एकत्रित हो प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देवें। प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त सदस्य भी इस कार्यक्रम में सक्रिय रह कर किसी न किसी जिले में अवश्य भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनावें। समाचार पत्र तथा मीडिया में भी इसके प्रचार प्रसार की योजना बनावे तथा शिक्षक संदेश में भी समाचार भिजवाने का ध्यान रखें।

भवदीय

संलग्न- ज्ञापन के प्रारूप की प्रति

(देवलाल गोचर)
महामंत्री

पंजीकृत संख्या 72/54–55
www.rssrashtriya.org

।। वन्दे मातरम्।।

Tel. : 0141-2377799
Fax : 0141-2362212
E-mail : rss.rashtriya@gmail.com

# राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302 001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोषचन्द सुराणा, श्यामसुन्दर शर्मा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, उमराव लाल वर्मा

Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIFTF, AISTF, R.R.K.M. & E.I.,

| प्रहलाद शर्मा | रामावतार शर्मा | देवलाल गोचर |
|---|---|---|
| अध्यक्ष | सभाध्यक्ष | महामंत्री |
| 9414056109 | 9166616080 | 9414403756 |

## ज्ञापन प्रारूप

दिनांक: 10.01.2017

माननीया मुख्यमंत्री महोदया,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

द्वारा:– जिला कलक्टर महोदय।
जिला.....

विषय: शिक्षकों की छठें वेतनमान में रही विसांगतियों को दूर करते हुए केन्द्र के अनुरूप सातवाँ वेतनमान लागू करने हेतु ज्ञापन।

महोदया,

निवेदन है कि राज्य के शिक्षकों को अन्य कर्मचारियों के अनुरूप पाँचवे वेतनमान तक केन्द्र के समान वेतनमान दिया जाता रहा था किन्तु छठे वेतनमान में राजस्थान में शिक्षकों को केन्द्र के अनुरूप पे बैण्ड एंव ग्रेड पे नही दिये गये। विधानसभा चुनाव 2013 के समय इस विसंगति को स्वीकार करते हुए भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में इसे दूर करने की घोषणा की गई थी। लेकिन सरकार के 3 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद अभी तक इन विसंगतियों को दूर नही किया गया है । इस कारण शिक्षको को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है।

केन्द्र में दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागु कर दिया गया है और राजस्थान में भी इन्हे लागु किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के शिक्षक छठे वेतन मान की विसंगतियों को दूर किये बिना सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू किये जाने से होने वाले भारी आर्थिक नुकसान से आशंकित है और उनमें घोर असंतोष व्याप्त है। संलग्न विवरण पत्र में प्रारम्भिक तौर पर इस नुकसान का आकलन आपके अवलोकनार्थ तैयार किया गया है। यहा यह भी ध्यातव्य है कि राज्य में अन्य कई संवर्गो के ग्रेड–पे व पे– बैण्ड में संशोधन किया जा चुका है।केवल शिक्षको को ही उन के वाजिब हक से वंचित करने से यह असंतोष द्विगुणित हो रहा है।

आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र अनुसार विसंगतियों का अवलोकन कर उक्त विसंगतियों को दूर कर राजस्थान में भी शीघ्र ही 1 जनवरी 2016 से केन्द्र के अनुरूप सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागु कर अनुगृहीत करें।

जिलाध्यक्ष
जिला.....

जिलामंत्री
जिला.....